

विजय तमिलनाडु के 9 वें मुख्यमंत्री बने

शपथ लेते वक्त स्पीच देने लगे तो राज्यपाल ने टोका, पहला ऑर्डर 200 यूनिट फ्री बिजली का

चेन्नई, 10 मई 2026। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने रविवार सुबह 10.15 बजे तमिल में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। थलापित विजय शपथ लेते समय निर्धारित लाइनों के अलावा और बातें बोलने लगे। इस पर राज्यपाल अलेंकर ने उन्हें टोक दिया और कहा कि वही पढ़ें जो लिखकर दिया है। सीएम विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉ. केजी अरुणराज, केए. सेगोडियन, पी. वेङ्कटरमणन, आर. निर्मलकुमार, राजमोहन, डॉ. टीके प्रभु, सेल्वी एस कोर्तना शामिल हैं। ये सभी विजय की पार्टी तमिलनाडु के विधायक हैं। सहयोगी दलों के किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। सीएम बनते ही विजय एक्शन में आए और दस्तावेजों का पहला सेट साइन किया। इनमें 200 यूनिट फ्री बिजली देने, महिला सुरक्षा दल और एंटी ड्रग्स स्कवाड बनाने के आदेश शामिल हैं।

नवीन पटनायक ने विजय को बधाई दी...

बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने विजय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, विजय को सीएम बनने पर बधाई। उम्मीद है कि तमिलनाडु नई लीडरशिप के नेतृत्व में और ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और तेजी से विकास करेगा।

सीएम बनते ही एक्शन में विजय, पहला ऑर्डर 200 यूनिट बिजली फ्री

सीएम जोसेफ विजय ने शपथ लेते ही एक्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल बनाने वाली फाइल साइन की। सीएम विजय ने अपने पहले संबोधन में कहा कि वे किसी भी शाही खानदान से नहीं हैं, लोगों ने ही उनका स्वागत किया और उन्हें स्वीकार किया। इसलिए झूठे वादों से लोगों को धोखा नहीं देंगे। सीएम विजय ने बताया कि पिछली डीएमके सरकार पर राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लाने का आरोप लगाया।

विजय ने शपथ के दौरान कहा...

मैं सी. जोसेफ विजय भारत की संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखूंगा और अपने विवेक के अनुसार



तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने विजय, राहुल गांधी बोले... राज्य ने नई पीढ़ी और नई राह को चुना

तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए अभिनेता से नेता बने विजय ने रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद राहुल गांधी ने विजय को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तमिलनाडु ने 'नई पीढ़ी, नई आवाज और नई राह' को चुना है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि तमिलनाडु की जनता ने बदलाव के पक्ष में अपना फैसला दिया है। राहुल ने उम्मीद जताई कि विजय राज्य की जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।



खरगे ने दी विजय को बधाई...

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि लंबे समय से राज्य की राजनीतिक और सामाजिक चेतना को परिभाषित करने वाले आदर्श टीवीके प्रमुख के नेतृत्व में सरकार को आगे भी दिशा देते रहेंगे। खरगे ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मैं उन्हें, तमिलनाडु के कथम (टीवीके) पार्टी और पूरे गठबंधन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।

कांग्रेस ने डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा : पीएम मोदी

कर्नाटक में 'आर्ट ऑफ लिविंग' के प्रोग्राम में कहा... सत्ता बदलते ही कांग्रेस पलटी



बेंगलुरु, 10 मई 2026। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा... कांग्रेस और डीएमके के बीच पिछले 25-30 साल से करीबी संबंध रहे हैं। डीएमके ने कई बार कांग्रेस को संकट से बाहर निकाला। 2014 से पहले केन्द्र में 10 साल तक चली कांग्रेस सरकार भी डीएमके के समर्थन की वजह से ही टिकी रही। डीएमके ने हर समय कांग्रेस के हित में काम किया, लेकिन जैसे ही सत्ता का समीकरण बदला, कांग्रेस ने पहले ही मौके पर डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा दिया। उन्होंने यह बात 'आर्ट ऑफ लिविंग' के 45वें स्थापना दिवस समारोह में कही।

400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी 100 सीटें भी नहीं जीत पा रही : पीएम

पीएम ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि 40 साल पहले 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी पिछले तीन चुनावों में मिलकर भी 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इसके बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का अहंकार इतना ज्यादा है कि वे अपनी हार के लिए पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पीएम ने बीजेपी और एनडीए की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि देशभर में पार्टी को बड़ा समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि पुदुचेरी में लगातार दूसरी बार और असम में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को पहली बार इतना बड़ा जनादेश मिला है। उन्होंने इसे पार्टी के लिए अहम राजनीतिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा यह भी कहा कि दो हफ्ते पहले गुजरात में हुए पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। उनके मुताबिक, गुजरात बीजेपी ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीएम ने कहा- आपको याद होगा कि महज 10 साल पहले बंगाल में हमारे पास सिर्फ 3 विधायक थे। लेकिन आज वहां भाजपा की सरकार है और 200 से अधिक विधायक हैं।

कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोखा देना जानती है : पीएम

पीएम ने कहा... कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोखा देना जानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद झूठ बोलती है और उसकी गारंटियां भी झूठी होती हैं। कर्नाटक में पिछले तीन साल से यही स्थिति देखने को मिल रही है। राज्य सरकार जनता की समस्याएं हल करने के बजाय अपना ज्यादातर समय अंदरूनी झगड़े सुलझाने में बिता रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह तक तय नहीं हो पा रहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री कितने दिन तक पद पर रहेंगे और दूसरे नेता को मौका मिलेगा या नहीं।

एयर इंडिया ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला

नई दिल्ली, 10 मई 2026। एयर इंडिया ने पिछले तीन सालों में 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इन कर्मचारियों पर नैतिक नियम तोड़ने के आरोप थे। एयरलाइन के सीईओ कैप्टेन विल्सन ने कहा है कि कंपनी में सही तरीके से काम करना जरूरी है। एयर इंडिया में इस समय करीब 24,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह जानकारी कर्मचारियों के साथ हुई एक टाउन हॉल मीटिंग में साझा की गई। विल्सन ने बताया कि कई कर्मचारियों को प्लेन में सामान की तस्करी और बिना शुल्क अतिरिक्त सामान ले जाने जैसे मामलों में हटाया गया। इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए बने एम्प्लॉई लीजर ट्रेवल सिस्टम के गलत इस्तेमाल के मामले भी सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक, एयर इंडिया ने इस सिस्टम में हजारों कर्मचारियों की गड़बड़ियां पकड़ी हैं। कंपनी ने ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने और नियम सख्त करने जैसे कदम भी उठाए हैं। एयर इंडिया इस समय आर्थिक दबाव का सामना कर रही है और खर्च कम करने के उपाय लागू कर रही है। कंपनी ने कर्मचारियों के सालाना वेतन बढ़ोतरी को कुछ समय के लिए टाल दिया है। साथ ही गैर-जरूरी खर्च कम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों से फिजूल खर्च रोकने और मुश्किल हालात को समझने की अपील की है। एयरलाइन का कहना है कि मौजूदा हालात में हर स्तर पर लागत नियंत्रण जरूरी है। एयर इंडिया के सीईओ ने कर्मचारियों से कहा कि अगर मिडिल ईन्ट में हालात नहीं सुधरे तो यह साल कंपनी के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को मार्च, 2026 तक खत्म हुए वित्त वर्ष में 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। कंपनी का कहना है कि वैश्विक हालात, ईंधन खर्च और दूसरे आर्थिक दबावों का असर कारोबार पर पड़ रहा है।



पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा 7 दिनों की इंडी रिमांड पर... 100 करोड़ के जीएसटी घोटाले का आरोप

चंडीगढ़, 10 मई 2026। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इंडी (इंडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को गुरुग्राम के सेरांस कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। शनिवार देर रात इंडी ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता और पंजाब कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को करीब 100 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, इंडी ने संजीव अरोड़ा की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन वकीलों की दलीलों के बाद मजिस्ट्रेट मुनमुन चौधरी ने 7 दिनों की रिमांड मंजूर की। संजीव अरोड़ा के वकील अर्जुन ने इंडी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि इंडी ने 5 मई को मामला दर्ज किया और 9 मई की सुबह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस बीच कोई वास्तविक जांच नहीं की गई। वकील ने दावा किया कि उन्हें अभी तक एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई है। अदालत ने अब मंत्री को 16 मई को दोबारा गुरुग्राम कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। इंडी अधिकारियों के अनुसार, यह जांच 100 करोड़ रुपये से अधिक के मोबाइल फोन की कथित फर्जी जीएसटी खरीद के इवेंट-गिद घूम रही है। जांचकर्ताओं का दावा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, नियाँ से जुड़े जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक का गलत तरीके से लाभ उठाने के लिए दिल्ली स्थित फर्जी फर्मों के माध्यम से फर्जी खरीद बिल तैयार किए गए थे। इस कार्रवाई के दौरान, एजेंसी ने हैम्प्टन स्कॉर्ड रिपल्ट लिमिटेड के परिसरों की भी तलाशी ली, जो इस मामले में जांच के घेरे में हैं। मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर हुई इंडी की छापेमारी पर पंजाब के आप प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा, हमें पता चला है कि इंडी की टीमों फिर से संजीव अरोड़ा के घर पहुंची हैं।



असम में फिर से 12 मई को मुख्यमंत्री बनेंगे हिमंता बिस्वा सरमा

बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए, सरकार बनाने का पेश किया दावा

गुवाहाटी, 10 मई 2026। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। असम की राजनीति में अपनी रणनीतिक कुशलता और विकासवादी छवि के लिए मशहूर सरमा 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने रविवार (10 मई) को ऐलान किया कि हिमंता बिस्वा सरमा को असम में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। इससे उनके लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। असम में लगातार तीसरी



बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पहली बार 2016 में सत्ता में आई थी, जिसकी बागडोर सर्वानंद सोनोवाल के हथ में थी। नड्डा ने कहा कि

दलों असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने भी उनके नाम का समर्थन किया। इससे पहले रविवार सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें बाद में गठबंधन के सहयोगी दल भी शामिल हो गए। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नड्डा और सह-पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी उपस्थित रहे। गठबंधन नेता चुने जाने के बाद सरमा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विधायकों को संबोधित करते हुए पिछले महीने हुए चुनाव में मिले जनादेश के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से मिलेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से किया पेट्रोल-डीजल का संयम से इस्तेमाल का आह्वान

हैदराबाद, 10 मई 2026। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध में होमुज जलजलमध्य के बंद होने से वैश्विक ईंधन आपूर्ति पूरी तरह ठप पड़ी है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से पेट्रोल, डीजल और गैस का बहुत ही संयम से साथ उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आयातित पेट्रोल उत्पादों पर निर्भरता कम करने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भारत की अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में 9,377 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान हैदराबाद में कहा, पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत पर तो



और भी गंभीर असर हुआ है। उन्होंने कहा, युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। यहां तक की उनकी कीमतें आसमान को भी पार कर गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत के पास बड़े-बड़े तेल के कुएँ नहीं हैं। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल-डीजल, गैस, यह सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार, 6 विधायक बनाए गए मंत्री

भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडेय को मिली जगह...

लखनऊ, 10 मई 2026। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का आज दूसरी बार विस्तार हुआ है। 6 नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। इनमें भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर के नाम हैं। नए मंत्रियों में एक ब्राह्मण, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और 2 दलित वर्ग से हैं। वहीं, 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। इनमें राज्यमंत्री अजीत पाल और सोमेश तोमर का नाम है। उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फिलहाल विधान परिषद सदस्य। मनोज पांडे: ऊंचाहार से विधायक। समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए। कृष्णा पासवान खाना सीट से भाजपा विधायक हैं। 4 बार



विधायक और 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। सुरेंद्र दिलेर खैर सीट से विधायक। हथरस के पूर्व सांसद राजवीर सिंह दिलेर के बेटे हैं। हंसराज विश्वकर्मा भाजपा से एमएलसी। पिछड़ा वर्ग की राजनीति में मजबूत पकड़। कैलाश राजपूत: तिरवा से विधायक।

पहले बसपा में रहे। योगी सरकार ने पहला मंत्रिमंडल विस्तार 2024 के लोकसभा चुनाव ठीक पहले 5 मार्च को किया था। तब 4 नेताओं को मंत्री बनाया गया था। इनमें सुभासपा प्रमुख आ.एम. प्रकाश राजभर, सपा छोड़कर भाजपा में आने वाले दास सिंह चौहान, राष्ट्रीय

लोक दल के अनिल कुमार और भाजपा के सुनील शर्मा के नाम शामिल थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री को मिलाकर 54 मंत्री हैं। आज विस्तार के बाद ये 60 हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, मंत्रिमंडल में केवल 6 रिक्तियां हैं, इससे ज्यादा दो दूसरे दल से पाला बदल कर आए लोग हैं, क्या उन सभी को मंत्री पद से नवाजा जाएगा? एक समाज के कई विधायकों में से एक को चुना जाएगा तो आधार क्या होगा? जनता ये भी पूछ रही है कि आखिरी 9 महीनों में ये मंत्री बया कर लेंगे जब 9 साल में ये सरकार कुछ न कर सकी। उत्तर प्रदेश में भाजपा के 258 विधायक हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट' को लेकर पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर... पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया पर उठाए स्वाल

नई दिल्ली, 10 मई 2026। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर गंभीर स्वाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि परियोजना को

दी गई पर्यावरणीय मंजूरी अधूरी और अन्यायित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्टों के आधार पर प्रदान की गई है। जयराम रमेश का कहना है कि सरकार द्वारा जारी 'ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एफएचयू' में किए गए कई दूरे मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों और उपलब्ध

अध्ययनों से मेल नहीं खाते। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना पत्र साझा करते हुए कहा कि सरकार ने 01 मई को जारी एफएचयू में दावा किया था कि परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की व्यापक पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन मजबूत पर्यावरण प्रभाव आकलन

प्रक्रिया तथा विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर पहले भी 03 मई को विस्तृत प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लेकिन अब कुछ अतिरिक्त तथ्यों और तकनीकी बिंदुओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।



संपादकीय



बंगाल को पटरी पर लाने की चुनौती

पश्चिम बंगाल में जैसे ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वैसे ही ममता बनर्जी ने उसका उग्र विरोध करना शुरू कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। शीर्ष अदालत ने एसआइआर को न केवल सही माना, बल्कि उसे जारी रखने के आदेश भी दिए। यही नहीं उसने इस प्रक्रिया की निगरानी न्यायिक अधिकारियों को भी सौंप दी। जब चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की तो उसका भी ममता ने विरोध किया, जबकि यदि चुनाव के पहले और चुनाव के समय हिंसा नहीं हुई तो इसका श्रेय चुनाव आयोग को ही जाता है।

इसके बाद भी ममता ने अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। इसीफा देने से इन्कार करके उन्होंने बचकाने राजनीतिक व्यवहार का ही परिचय दिया है। निःसंदेह अन्य राज्यों की तरह बंगाल में भी मृत, स्थानांतरित और दोहराव वाले लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, लेकिन इसके आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि तुणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी एसआइआर के कारण हरी। यह आरोप इस तथ्य से झूठा साबित होता है कि जिन 20 सीटों पर सबसे अधिक नाम काटे गए, उनमें से 13 में टीएमसी जीती।

इससे इन्कार नहीं कि एसआइआर में कुछ विमर्शितायें रही होंगी, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया सौ प्रतिशत सही नहीं होती, पर टीएमसी की हार के लिए एसआइआर को दोष देना इस सच से मुंह मोड़ना है कि ममता का शासन कुशासन का पर्याय बन गया था। 15 वर्षों से सत्ता पर आसीन ममता ने मुस्लिम तुष्टीकरण की हद्द पार कर दी थी। इसकी प्रतिक्रिया में हिंदू भाजपा के पक्ष में गोलबंद हुए और इसी कारण उसे अप्रत्याशित जीत मिली। टीएमसी की पराजय इस कारण भी हुई, क्योंकि खुद ममता भी अलोकप्रिय हो गई थी। इसका कारण था उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से अवैध वसूली और लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करना।

बंगाल में महिला असुरक्षा का मुद्दा भी सतह पर आया, क्योंकि आरजी कर मेडिकल कालेज की डाक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या और संदेशवाली में हिंसा जैसे महिलाओं से दुर्व्यवहार की घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। इससे टीएमसी के प्रति सत्ता विरोधी माहौल और अधिक गहराया। ममता अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय जिस तरह यह कह रही है कि वे हारी नहीं, बल्कि उन्हें हराया गया है, वह उनकी खीझ ही है।

बंगाल में आजादी के बाद पहले कुछ दशकों तक कांग्रेस का शासन रहा, फिर वाम दल तीन दशक से भी अधिक समय तक सत्ता में रहे। जब वाम दलों का शासन कुशासन का पर्याय बना तो लोगों ने परिवर्तन के नारे के साथ उन्हें चुनौती देने वाली ममता का साथ दिया, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने भी वाम दलों वाले तौर-तरीके अपना लिए। इसका एक कारण यह भी रहा कि वाम दलों के तमाम नेता और कार्यकर्ता टीएमसी में आ गए थे। एक समय जो ममता बांग्लादेशी युष्पटियों का विरोध करती थीं, वही सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लोभ में उनकी अनदेखी करनी लगीं। वे इस सच से इन्कार करती रहीं।

जीवन का सुख-चैन छीनता अहंकार



डॉ. प्रतिक भट्टनाग

भले ही हमने शारीरिक रूप से मानवी देह पाया है, लेकिन क्या हम इंसान है या इंसान कहलाने के पात्र है? आज के दौर में इंसान बनकर जीने वाले दुर्लभ होते जा रहे हैं। आइये पहले हम स्वयं से जानते है कि, इंसान किन्हें कहते हैं। दूसरों की खुशी में खुश होना, दूसरों के दुःख में दर्द महसूस होना, दूसरों भावनाओं को समझना, उसकी कद करना। अपने स्वार्थ को दूर रखकर हमेशा दूसरों के भलाई का ख्याल करना। देश और समाज के विकास के लिए तत्पर रहना, यथोचित हर संभव मदद करना, मानव कल्याण का जज्बा बनाने रखना। झूठे दिखावे से बचना, लोगों से ईर्ष्या भाव न करना। प्रकृति, पशु-पक्षियों और जंगल की रक्षा करना। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा, रंगरूप पर आधारित भेदभाव को न मानकर समस्त मानवी समाज को एक स्तर पर मानकर मानवी सेवा विकास को सर्वोपरि मानना। कथनी-करीनी में अंतर न करना। नशाखोरी, भ्रष्टाचार, चरित्रहीन व्यवहार, अन्यों से दुर्व्यवहार, अपराध, भेदभाव से अलिस होकर सकर्मको को ही हमेशा प्राथमिकता देना। यह सभी इंसानियत की विशेषता है, जो इंसानों में होनी चाहिए। अगर ये सभी विशेषता हम में है, तो हम इंसान है, नहीं जानवरों को भी लज्जित कर दे, ऐसे घृणात्वक

कलकित करनेवाली दुःखद घटनाएं तो हमारे आसपास रोजाना होती ही है और हम अंधे मूंदकर बुजदिल की जिंदगी काटते हैं। हमारे आसपास के इस कलह भरे वातावरण में हर कोई झूठ का मुखौटा पहनकर खुद को इंसान दिखाने का प्रयत्न कर रहा है और यही वातावरण अहंकार की भेट चढ़कर जीवन का सुकून छीन रहा है। आज रिश्ते-नाते, शार्दियां तोड़ने में अहंकार मुख्य भूमिका में है। दुनिया को बताने के लिए कारण कुछ भी बताये लेकिन आज विभिन्न देशों में चल रहे युद्ध का कारण अहंकार भी है, जिससे बड़ी मात्रा में मासूमों की जान जा रही है, पर्यावरण, धन का अपव्यय हो रहा है और पूरी दुनिया पर इसका गंभीर असर हो रहा है। अनेक बार रिश्तेदार, आस-पड़ोसी, परिचित अहंकार के कारण जिंदगी भर बात नहीं करते, उससे जिंदगी में क्या हासिल हो जाता है, पता नहीं।

क्या आप जानते है कि, जब भी हम क्रोध, चिढ़, ईर्ष्या, तनाव या बुरे विचारों से भर उठते है, तब उसका सीधा असर हमारे खुद के ही स्वास्थ्य पर गंभीर असर करता है, अर्थात दूसरों पर गुस्सा करना हमारे जान को जोखिम में डालता है। आजकल तो नाम के लिए या दिखावे के लिए हम खूब आधुनिक होने का दम भरते है, लेकिन विचारों और संस्कारों से हम लगातार पिछड़ते ही जा रहे है। राह चलते हुए गलती से किसी को धक्का भी लग जाये तो, इंसानियत दिखाने के बजाय गाली-गलौज, धमकी, धीस दिखाने खुद के वर्चस्व को साबित करने की होड़ लग जाती है फिर बात मारपीट और कई बार हत्या तक पहुंच जाती है। हमारे रिश्ते-नाते, आस-पड़ोस या परिचित में किसी के घर कोई खुशखबर तो तो हम मन के मन में, जलन से भरते है, लोगों की मेहनत को नजरअंदाज करके खुद को किस्मत को कौंसेते है, कि दूसरों के साथ क्यों अच्छा होता है, हमारे साथ क्यों नहीं। झूठ



दिखावा और खुद का स्टैंडर्ड ऊंचा दिखाने के चक्कर में अक्सर बर्बादी के मुहाने में पहुँच जाते है, ये आज के समाज का घिनोना सच है। मनुष्य का अहंकार उसका सुख-चैन छीन लेता है और सुंदर शांत जीवन का मार्ग दुर्गम बना देता है। अहंकार मनुष्य के जीवन को विनाश की ओर धकेलता है, जैसे मनुष्य खुद ही अपनी मौत के लिए चिता सजा रहा है। हमारे आसपास बहुत से बुरे घटनाओं से अनगिनत लोगों के दुःखद अंत की खबरें हमें झंझोड़ देती है, उदाहरण के लिए आज बहुत से अभिभावक बच्चों को विदेश भेजते है या बड़े शहरों में भेजते है और अहंकार से गर्वित होते है कि उनके बच्चे विदेशों में स्थायिक हो चुके है, परंतु अनेक बार ये ही बूढ़े माँ-बाप भी जाते है, फिर भी उनके बच्चे अंतिम संस्कार में उपस्थित दर्शाना भी मुनासिब नहीं समझते, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। दुनिया भर में हजारों ऐसे महान शख्सियत है जो नाम, शोहरत, रतबा, पैसा होने के बावजूद सरल और नुशाबूत जीवन यापन करते हैं, अनेक महान लोग दुनिया से चले जाने के बाद उनकी जिंदगीभर की कमाई में केवल कुछ जोड़ी कपड़े और किताबों का संग्रह देखने मिलता है, थोड़ी-बहुत

संपत्ति होती भी है तो वे उसे दान कर चुके होते है, जबकि वे चाहते तो करोड़ों, अरबों रुपयों की संपत्ति बना सकते थे, लेकिन तब वे शायद अपने कर्मों से महान नहीं बन पाते। अहंकार अक्सर हमारी झूठी आत्म-छवि को बचाने के लिए असंलियत को तोड़-मरोड़ देता है, जिससे गलतियाँ मानना या आलोचना स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है, अहंकार अगर हावी हो जाये तो खुद को सही साबित करने में लग जाते है, जिससे टकराव उत्पन्न होता है। अहंकार में मनुष्य खुद को महान या सर्वगुण संपन्न समझता है जिससे दूसरों के प्रति हीन भावना उत्पन्न होती है। अहंकार हमें दूसरों की राय और भीतिक सफलता की बहुत ज्यादा परवाह करने पर मजबूर करता है, जिससे हमें चिंता और नाखुशी होती है, जीवन में उदासी छाती है। इससे लोग अच्छ करने के बजाय अच्छ दिखने को या शॉर्टकट लेने को प्राथमिकता देना पसंद करते है। अहंकार जिंदगी पर गहरा असर डालता है, बड़ा हुआ अहंकार कुछ नया सीखने में रुकावट डालता है, होने के डर से विकास को रोकता है, और के बाद उनकी जिंदगीभर की कमाई में केवल कुछ जोड़ी कपड़े और किताबों का संग्रह देखने मिलता है, थोड़ी-बहुत

श्रीराम के जीवन में शक्ति और विनम्रता का अद्भुत समन्वय!



आत्मराम यादव पीवल
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण का पठन करें या गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की मीमांसा करें, या मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के चरित्र की त्रिवेणी में गोते लगाईयेगा, हमें हर जगह उनके जीवन में बल और विनम्रता, दोनों एक साथ दिखाई देते है जो एक दुर्लभ संयोग माना जाता है। जिस व्यक्ति में विद्यावल, शरीर बल और धन का बल होता है, उसमें कभी-कभी श्रेष्ठता मनोर्ध्वक का निर्माण हो जाता है। बल के मद में व्यक्ति की उच्चतर भावनाएँ भी कठोर हो जाती है। किन्तु जब बलवान व्यक्ति में विनम्रता का गुण आता है, तब उसका जीवन सोने पे सुहागा हो जाता है, उसका चरित्र सुदृढ़ हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र के जीवन में हम शक्ति और विनम्रता का विलक्षण समन्वय पाते हैं। श्रीराम का पराक्रम अतुलनीय था। उनके गुरु विश्वामित्र के द्वारा उन्हें विभिन्न शक्तियों और दिव्यस्त्र प्राप्त हुए थे। इसके अलावा उन्हें सम्पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, किन्तु उनके शब्दों में हम कहें भी विद्या अथवा शक्ति का दंभ नहीं दिखता था, बल्कि उनके प्रत्येक शब्दों से मानो विनम्रता प्रस्फुटित होती थी। किन्तु

आवश्यकता पड़ने पर वे वज्र के समान कठोर भी हो जाते थे। राजा जनक की सभा में धनुष-भंग के पश्चात् जब क्रोध में उन्मुक्त परशुराम जी आते हैं और यह पूछते हैं कि उनके गुरु शिवजी का धनुष किसने तोड़ा, उस समय श्री राम जी के उतर में विनय की पराकाष्ठा दिखाई देती है। परशुराम जी को आवेशावतार कहा जाता है। परशुराम जी शिव-धनुष तोड़ने वाले को मृत्यु-दंड ही देने आए थे। सभा में और भी अनेक राजा उपस्थित थे। उन्होंने जब परशुराम जी को देखा, तो भय के मोरे कांपने लगे और उन्हें प्रणाम करने लगे। श्री राम जी ने भी उन्हें प्रणाम किया। किन्तु श्री राम जी के प्रणाम करने और अन्य राजाओं के प्रणाम करने में अंतर था। अन्य राजाओं की विनम्रता भय प्रसूत थी, किन्तु श्रीराम ने तो अपने विनम्र स्वभाव के वशीभूत ही प्रणाम किया।

जब भरी सभा में किसी में भी यह कहने का साहस नहीं हुआ कि किसने धनुष तोड़ा, तब गोस्वामी तुलसीदास जी बालकाण्ड में श्रीराम को आगे करके लिखते है कि श्रीराम ने परशुराम से कहा- नाथ शम्भू धनु भंजनि हारा, होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ अर्थात्- शिव-धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। परशुराम जी ने सोचा होगा कि जिसने धनुष तोड़ा है, वह सीना तान कर खड़ा होगा। किन्तु श्रीराम के विनय रूपी जल ने परशुराम जी की क्रोधाग्नि को पूर्ण रूप से शांत कर दिया।

व्यक्ति को जब कोई बहुत बड़ी सफलता मिलती है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास न हो, तो उसका जीवन बोझ ढोने वाले पशु के समान हो जाता है। किन्तु यह भी देखना है कि यह आत्मविश्वास कहीं दंभ अथवा अहंकार का रूप न धारण कर ले। अच्छे कार्य का श्रेय तो हम ले लेते है, किन्तु कार्य में

जब कोई त्रुटि दिखती है, तो हम उसे किसी दूसरे के मर्त्ये मढ़े हैं। श्रीरामजी का चरित्र हम यदि देखें, तो वे सफलता अथवा अच्छे कार्यों का श्रेय सदैव दूसरों का है जब रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने चानर सेना की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारे ही बल (सहयोग) से मैंने रावण को मारा है। यह राम जी का अपने भक्तों के प्रति प्रेम और अहंकार हीनता (निराभिमानी स्वभाव) को दर्शाता है, जहाँ वे अपनी जीत का यश अपनी सेना को देते हैं। रावण को पराजित करने के बाद वे युद्ध-विजय का श्रेय वानरों और बाहुल्य को देते हुए कहते हैं - चितड़ सबन्हि पर कीन्ही दाया। बोले मुदुल बचन रघुराया। तुम्हरे बल में रावनु मारयो। तिलक बिभीषण कहै पुनि सारयो॥2॥

श्री राम रावण वध कर वनवास की अवधि पूरी कर अयोध्या लौटते है तब वे गुरुदेव विशिष्ट के सामने वानरों की प्रशंसा में कहते हैं- ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहै बरे ॥ मम हित लागि जन्म इन् हारे। भरतहु ते मोहि अधिक पियारे॥4॥ - हे मुनि। सुनिए। ये सब मेरे सखा है। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े के समान हुए जिन्होंने मेरे हित के लिए इन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। ये मुझे भरत से अधिक प्रिय है। पुण्य विमान में माता सीता एवं अन्य सहचरों के साथ जब वे अयोध्या प्रत्यागमन करते हैं, तब मार्ग में भी माता सीता से वे हनुमान, अंगद आदि के पराक्रमों का बखान करते हैं।

विनम्र व्यक्ति में ही विद्या की पूर्णता होती है। जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार यथार्थ विद्यावान व्यक्ति भी नम्र हो जाता है।

छोटे-छोटे निरंतर प्रयासों से खुलते बड़े सफलता के द्वार



संजय ठाकुर,
रायपुर छत्तीसगढ़

गांधीजी का प्रसिद्ध कथन है- पहले वे आपको नजर अंदाज करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और अंत में आप जीते जाएंगे।

मानव जीवन संघर्ष, परिश्रम, धैर्य और निरंतर प्रयासों की एक लंबी कहानी है। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए उनकी सफलता किसी एक दिन की चमत्कारी घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों तक किए गए छोटे-छोटे सतत प्रयासों का बड़ा परिणाम थी। सफलता का कोई सुगम और सरल नहीं होता। वह धीरे-धीरे तपकर, गिरकर, संभलकर और निरंतर आगे बढ़ने से प्राप्त होती है। जिस प्रकार छोटी-छोटी बूँदें मिलकर विशाल सागर का निर्माण करती है, उसी प्रकार मनुष्य के छोटे-छोटे प्रयास जीवन में बड़ी उपलब्धियों का आधार बनते हैं। किसी शायर ने कहा है:-

पानी की छोटी बूँदों ने बढकर समंदर बना दिया, छोटे-छोटे प्रयासों ने आदमी का मुकद्दर बना दिया।

आज का समय त्वरित परिणामों का समय माना जाता है। लोग चाहते हैं कि उन्हें बिना संघर्ष के तुरंत सफलता मिल जाए। किन्तु प्रकृति का नियम है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे लंबे समय तक किया गया श्रम और अनुशासन छिपा होता है। किसान बीज बोने के बाद प्रतिदिन उसकी देखभाल करता है। वह जानता है कि फसल एक

दिन में नहीं उगेगी, परंतु यदि उसका प्रयास निरंतर रहेगा तो एक दिन खेत अवश्य लहलहाएगा। यही नियम मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताएँ झेली थीं। जब उनसे पूछा गया कि वे हजार बार असफल कैसे हुए, तब उन्होंने कहा कि:-

मे असफल नहीं हुआ, मैंने केवल हजार ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते।

यह कथन हमें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक चरण होती है। यदि मनुष्य हर असफलता के बाद पुनः प्रयास करता रहे, तो अंततः सफलता उसके कदम चूमती है। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर निरंतर संघर्ष करते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प और सतत प्रयास किसी भी बड़ी शक्ति को झुका सकते हैं। गांधीजी का प्रसिद्ध कथन है:-

यह कथन केवल राजनीतिक संघर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करता है, तो प्रारंभ में लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, किन्तु अंततः वही व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जीवन भी छोटे-छोटे प्रयासों की महान कहानी है। साधारण परिवार में जन्म लेने वाले कलाम साहब ने कठिन परिस्थितियों में समाचार पत्र बंद, पढ़ाई की और अपने सपनों को कभी मले नहीं दिया। निरंतर परिश्रम और अनुशासन के बल पर वे मिसाइल मैन कहलाए और देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचे। उन्होंने कहा था:-

सपना वह नहीं जो आप सोते



समय देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने न दे।

उनका यह विचार युवाओं को निरंतर प्रयास और लक्ष्य के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। केवल सपना देखने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए प्रतिदिन कर्म करना पड़ता है। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे आवश्यक है एक स्पष्ट लक्ष्य। बिना लक्ष्य के प्रयास दिशाहीन हो जाते हैं। जिस प्रकार नाविक बिना दिशा के समुद्र में भटक जाता है, उसी प्रकार लक्ष्यहीन मनुष्य भी अपने जीवन की ऊर्जा व्यर्थ कर देता है। यदि मनुष्य एक निश्चित लक्ष्य तय कर ले और उस दिशा में प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा कार्य करता रहे, तो धीरे-धीरे सफलता उसके निकट आने लगती है। इतिहास गवाह है कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आत्मविश्वास और निरंतर कर्म का संदेश दिया था। उनका प्रसिद्ध वाक्य:-

उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाय।

यह केवल प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। मनुष्य को कठिनाइयों, आलोचनाओं और असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। निरंतर आगे बढ़ते रहना ही सफलता का मार्ग है।

प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है। नदी पर्वतों से टकराकर रुकती नहीं, बल्कि अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। चींटी बार-बार गिरने के बाद भी दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती रहती

बजाय हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित करते है, जिससे समयोजित करने की क्षमता, गहरे रिश्ते और उत्पादकता बढ़ती है।

खुद को समझने के लिए अपने कार्य, व्यवहार, स्वभाव और इसका अन्यों पर असर इन सभी बातों का आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है, खुद का विश्लेषण करने के लिए समय निकालें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहाँ हमारा अहंकार हमारे निर्णयों और बातचीत को प्रभावित कर रहा हो। जीवन में सबसे जरूरी शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, पोषक आहार है, और मन को संतोष है तो जीवन सुख से बीता है, लेकिन लोग इसे प्राथमिकता देते के बजाय अहंकार, झूठा दिखावा और घमंड में सुकून खो बैठते हैं। लोग आज के दौर में, घर के आगे कोई पड़ हो तो उसे काटकर वह आतिक्रमण करना चाहते है, तबकि घर का दायरा बढ़ाया जा सके, लेकिन ऐसी सोच ने पुरे देश में तापमान बढ़ाया है, यह किसी को नजर नहीं आता, हर कोई स्वार्थ के लिए जीते हुए प्रतीत होता है। स्वार्थ से अपना ध्यान हटाकर समाधानी सोच अपनायें। विनम्रता और सीखना अपनाएँ, मानें कि हमको सब कुछ नहीं पता। सफलता के लिए नतीजों पर नहीं, कोशिश पर ध्यान दें। मैं हमेशा ही सही हूँ वाली सोच छोड़ दे। अपना ध्यान अपनी चिंताओं से हटाकर दूसरों की सेवा करने पर लगाएँ, सत्कर्म करें। रोजाना ध्यान योग या शान्त सोच-विचार के लिए समय निकालें। अच्छे विचारों के लोगों से जुड़े, हेलदी हॉबी अपनाएँ, प्रकृति की रक्षा प्रत्येक की जिम्मेदारी समझें। महान समाजसुधारकों के आदर्श, सोच को जीवन में अपनाया। अच्छे काम करने का सुकून दुनिया में बेशकीमती है, छोटी सी जिंदगी है इसे तनावमुक्त रखकर हँसते मुस्कुराते हुए बिताएँ। अहंकार एक धीमा जहर है, जो इंसान के गुणों को मार देता है।

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह सहज हदा, मध्यप्रदेश

आज का दौर चुनौतियों से भरा है। बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता ने लाखों युवाओं के सपनों को कुचल दिया है। सोशल मीडिया पर चमकती जड़ियाँ देखकर वे अपनी किस्मत को कौसेते हैं और शकियत करते हैं कि उन्हें जन्म से न धन-दौलत मिली, न संपत्ति की विरासत। लेकिन एक साधारण सा वाक्य इस धमकी को तोड़ता है : जिन लोगों को विरासत में पैसा नहीं मिलता, उन्हें विरासत में मेहनत मिलती है। यह संदेश न केवल प्रेरक है, बल्कि जीवन की कठोर सच्चाई को उजागर करता है। यह उन नौजवानों के लिए मशाल की तरह है जो गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर अपनी और अपने परिवार की तकदीर बदलना चाहते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और

विरासत, मेहनत और कामयाबी, अपनी कहानी खुद लिखिए

लाखों युवा रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, यह संदेश और भी प्रसंगिक हो जाता है। विरासत का अर्थ सिर्फ भौतिक संपदा तक सीमित नहीं। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अनोखी नेमत दी है, मजबूत हाथ, तेज दिमाग, अटल इरादा और अंतहीन संघावनाएँ। मेहनत ऐसी विरासत है जो कभी समाप्त नहीं होती। जितनी बार आप इसे आजमाते हैं, उतनी ही यह मजबूत होती जाती है, जैसे धूप में पगड़ी की छांव बढ़ती जाती है। यह वही शक्ति है जो परिवार को गरीबी की दलदल से खींचकर समृद्धि के किनारे पहुँचा सकती है। इसे बोझ न समझें, बल्कि सुनहरा अवसर मानें। इतिहास इसकी गवाही देता है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जन्म

तमिलनाडु के एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ। अखबार बांटने से लेकर भारत के मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बनने तक का सफर मेहनत की मिसाल है। इसी तरह धीरूभाई अंबानी ने गुजरात की छोटी सी दुकान से रिलायंस जैसे साम्राज्य की नींव रखी। मेहनत ऐसी विरासत है कि विरासत में मिली मेहनत किसी भी ऊँचाई को छू सकती है।

जिंदगी हर इंसान को कम से कम एक बार कश्मिात फलने का सुनहरा मौका जरूर देती है। चाहे आप गांव का किसान का बेटा हों, छोटे शहर की फैक्ट्री में मजदूर या मध्यमवर्गीय परिवार से निकले छात्र। आज अगर हालात कठिन हैं, नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ाई का खर्च

न उठ पा रहा हो या पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ कंधों पर भारी पड़ रही हों, तो इसे ईश्वरीय संकेत समझें। अब जागने का समय है। इस अवसर को गंवाना न केवल व्यक्तिगत हार होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों से बेईमानी होगी। एक किसान का बेटा होता है, जो कल हरे-भरे खेत बन जाता है। ठीक वैसे ही आपकी आज की मेहनत कल आपके बच्चों की मजबूत नींव बनेगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार भारत में 4 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हैं। लेकिन यही युवा अगर मेहनत को अपनाएँ तो देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकते हैं। कामयाबी का असली मूल्य सिर्फ धन कमाना नहीं। यह वह ऊँचाई है जहाँ

आपका अतीत आपके वर्तमान पर गर्व करे। इतनी मेहनत करें कि आपकी सफलता मोहल्ले से निकलकर शहर, राज्य और पूरे देश में गूंज उठे। ठाकुर बंधुओं ने मुंबई की गलियों से निकलकर ठाकुर ग्रूप बनाया। चीन के जैक मा ने छोटे से अपार्टमेंट से अलीबाबा जैसा वैश्विक साम्राज्य खड़ा किया। सिर्फर से शुरू होकर शिखर छूना न केवल व्यक्तिगत विजय है, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा। यह लाखों युवाओं को संदेश देता है कि नामुमकिन कुछ नहीं। जब आप गरीबी से लड़ते हुए सफल होते हैं, तो आप मिसाल बन जाते हैं। हर जिंदगी एक खाली किताब है। कुछ लोग दूसरों की लिखी कहानियों का हिस्सा बनकर शिकार्यत करते रहते हैं।

लेकिन सच्चे विजेता अपनी दास्तान खुद रचते हैं। आज ही फँसला लें, हालात को बदलने का संकल्प। क्लम को अपने हाथ में थामें। हर बाधा को मोड़ बनाएँ। ऐसी कहानी लिखें जिसमें आप ही नायक हों, जो गरीबी से सलतनत बनाए, जड़ो जहद से फतह हासिल करें और मेहनत से अमर नाम कमाएँ।

अंत में, विरासत का धन क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन मेहनत कको स्थायी सम्मान, पहचान और गौरव प्रदान करता है। यह कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हिम्मत न हारें। बहाने त्यागें। मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएँ। हर सुबह नई जंग लड़ें। ऐसी शानदार जिंदगी रचें जो न केवल आपको अमर कर दे, बल्कि दुनिया को लंबे समय तक याद रहे। आपकी संतानें गर्व से कहेंगी, मेरे पूर्वजों ने खाली हाथों से इतिहास रचा।

जीत उसी की होती है, जिसको हारने का डर नहीं होता।

- अटल बिहारी वाजपेयी

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर-यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

तन्जरा जलाशय बदहाल



जर्जर नहरों और रिसते गेटों ने खोली विभाग की पोल

राजन पाण्डेय-
सोनहत/कोरिया, 10 मई 2026
(घटती-घटना)।

सोनहत क्षेत्र का तन्जरा जलाशय इन दिनों अपनी बदहाली को लेकर चर्चा का केंद्र बना हुआ है,कभी किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख सहाय माने जाने वाला यह जलाशय अब जल संसाधन विभाग की लापरवाही और कथित अनदेखी का

प्रतीक बन चुका है, जिले के विभिन्न जलाशयों और नहरों की खराब स्थिति लगातार सामने आने के बाद अब तन्जरा जलाशय की तस्वीर ने विभागीय दवाओं की वास्तविकता उजागर कर दी है, करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई सिंचाई व्यवस्था आज किसानों के लिए राहत नहीं बल्कि नई परेशानी का कारण बनती जा रही है।



कोरिया जल संसाधन विभाग का 'इजीमिटरिंग फेल्डो' : एक तरफ कलेक्टर सहेज रही है बुंद-बुंद पानी इधर जल संसाधन बहा रस जोश की बर्बाद...

स्पाटिकरण या तालाबों से बचने की कोशिश ? नहर में बहते पानी पर विभाग की सफाई से बढ़ा धिवादा

अब तो जागिए साहब ! टूटी नहर से खेत बने तालाब, सड़क पर बह रहा धुन्धुड़ा का पानी

अन्नदाताओं पर दोही मार

सिंचाई व्यवस्था हुई फेल ! तन्जरा जलाशय में बह रहा पानी, किसान परेशान

मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों खर्च, फिर भी तन्जरा जलाशय खस्ताहाल...

जल संसाधन विभाग की लापरवाही, नहरें टूटी, खेत डूबे, गेटों से बह रहा पानी...

तन्जरा जलाशय बना भ्रष्टाचार की मिसाल ? किसानों ने उठाए बड़े सवाल...

जर्जर नहरें, रिसते गेट और गायब मेंटेनेंस बजट से किसानों में भारी नाराजगी



कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी

अनित दुबे ने आरोप लगाया कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी एसी कमरों में बैठकर विकास का खाका तैयार कर रहे हैं, जबकि किसान अपनी फसलें बर्बाद होते देख रहा है, उन्होंने मांग की कि पिछले तीन वर्षों में जलाशयों के मरम्मत और मेंटेनेंस कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा खर्च की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ तो कांग्रेस किसानों के साथ आंदोलन करेगी।

जन सहयोग समिति ने मांगी फिजिकल ऑडिट

पुष्पेंद्र राजवाड़े ने कहा कि सोनहत क्षेत्र के सभी जलाशयों से बहता पानी विभाग की संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार का प्रमाण है, उन्होंने मांग की कि केवल कागजी जांच नहीं बल्कि तकनीकी टीम गठित कर सभी बांधों और नहरों की फिजिकल ऑडिट कराई जाए, साथ ही चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर तोस मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीणों के साथ विभागीय कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

किसानों की उम्मीदें अब प्रशासन पर टिकीं

तन्जरा जलाशय की स्थिति ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद ग्रामीण सिंचाई व्यवस्था क्यों बदहाल है, अब किसानों और ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन और जल संसाधन विभाग पर टिकी हैं, देखना यह होगा कि विभाग इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर व्यवस्था सुधाराता है या फिर तन्जरा जलाशय और यहां के किसान यूं ही अपनी बदहाली पर आसू बहाते रहेंगे।

नहरें जर्जर, खेतों में तबाही

तन्जरा जलाशय से निकली नहरों की हालत बेहद खराब बताई जा रही है, कई स्थानों पर नहरों की दीवारें टूट चुकी हैं, तो कहीं बड़े-बड़े दरारों से लगातार पानी रिस रहा है, परिणामस्वरूप पानी खेतों तक नियंत्रित रूप से पहुंचने के बजाय रास्ते में ही बहकर बर्बाद हो रहा है, कई किसानों के खेतों में जरूरत से अधिक पानी भरने से फसलें खराब होने लगी हैं, ग्रामीणों का कहना है कि जिन नहरों का उद्देश्य खेतों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना था, वही अब किसानों के लिए नुकसान का कारण बन गई है, खेतों में अनियंत्रित पानी घुसने से मिट्टी कटाव, फसल सड़ने और उत्पादन घटने जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, किसानों का आरोप है कि वर्षों से नहरों की सही मरम्मत नहीं कराई गई, जबकि कागजों में लगातार मेंटेनेंस दिखाया जाता रहा।

गेटों से लगातार बह रहा पानी

जलाशय के गेटों से लगातार हो रहा जल रिसाव विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, बांध के गेट किसी भी जलाशय की सुरक्षा और जल नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन तन्जरा जलाशय में यही व्यवस्था पूरी तरह कमजोर दिखाई दे रही है, स्थानीय लोगों के अनुसार कई महीनों से गेटों से पानी रिस रहा है, लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते गेटों की तकनीकी मरम्मत नहीं कराई गई तो भविष्य में यह बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकता है, लगातार जल रिसाव से न केवल पानी की भारी बर्बादी हो रही है, बल्कि सिंचाई के लिए सुरक्षित जल भंडारण भी प्रभावित हो रहा है।

आखिर कहाँ जा रहा मरम्मत का बजट ?

सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि जलाशयों और नहरों की मरम्मत के लिए हर साल जारी होने वाला लाखों-करोड़ों रुपये का बजट आखिर खर्च कहाँ हो रहा है, ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि कागजों में मरम्मत और सुधार कार्य दिखाकर बजट खर्च कर दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने रहते हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि वास्तव में समय-समय पर मरम्मत कार्य कराए गए होते तो आज नहरें टूटती नहीं और गेटों से पानी नहीं बहता। किसानों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और तकनीकी ऑडिट कराने की मांग उठाई है।

एसी कमरों से नहीं दिखती किसानों की परेशानी

ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने विभागीय अधिकारियों पर मैदानी निरीक्षण नहीं करने का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि अधिकारी कार्यालयों में बैठकर विकास के दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देखने कभी गांवों तक नहीं पहुंचते, इसी लापरवाही का परिणाम है कि सोनहत क्षेत्र के अधिकांश जलाशय और नहरें बदहाल स्थिति में पहुंच चुके हैं।

पंच संघ ने उठाई उच्च स्तरीय जांच की मांग

प्रेम सागर तिवारी ने कहा कि तन्जरा जलाशय की स्थिति केवल एक बांध की समस्या नहीं, बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली की पोल खोलने वाला मामला है, उन्होंने मांग की कि जिले के सभी बांधों और नहरों के मरम्मत कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि मरम्मत के नाम पर खर्च किया गया बजट आखिर कहाँ गया।

ग्राम पंचायत मंगोरा में गांजे की खेती का खुलासा

खड़गवां पुलिस ने 36 नग गांजे के पौधे किए जब्त, जांच जारी

संवाददाता-
खड़गवां, 10 मई 2026
(घटती-घटना)।

ग्राम पंचायत मंगोरा में अवैध गांजा खेती का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, खड़गवां पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव निवासी सर्वजीत सिंह की बाड़ी से 36 नग गांजे के पौधे बरामद किए गए हैं, सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गांजे के पौधों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



सूत्रों के अनुसार गांजे के पौधे काफी समय से लगाए गए थे और उनकी नियमित देखरेख भी की जा रही थी, बताया जा रहा है कि पौधों को खेत और आसपास के क्षेत्र में इस तरह छिपाकर लगाया गया था ताकि किसी को आसानी से संदेह न हो, लेकिन मामला उजागर होते ही पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है, इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की खेती किसके संरक्षण में चल रही थी और इतने दिनों तक प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, वहीं यह आशंका भी जताई जा रही है कि क्षेत्र में गांजा खेती का कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि अवैध खेती में

पटना में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, अवैध दवाएं बरामद

जिला स्तरीय स्वापक एवं मन : प्रभावी औषधियों के विरुद्ध चला अभियान

संवाददाता-
पटना/कोरिया, 10 मई 2026
(घटती-घटना)।

कोरिया जिले में स्वापक एवं मन:प्रभावी औषधियों तथा एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध जिला स्तरीय जन-जागरूकता अभियान लगातार जारी है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार सही दवा-शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार शीम के अंतर्गत 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है।



अभियान के बारहवें दिवस 08 मई को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं सहायक औषधि नियंत्रक के नेतृत्व में औषधि प्रकोष्ठ की टीम द्वारा पटना क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई की गई। इस दौरान पटना पुलिस विभाग के साथ संयुक्त टीम बनाकर मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर तेंदुआ चौक के पास दो महिलाओं से अवैध रूप से रखी गई औषधियां बरामद की गईं, मामले में पुलिस विभाग द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, अभियान के तहत पटना क्षेत्र के दवा एवं

खाद्य व्यापारियों को बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों को स्वापक एवं मन:प्रभावी औषधियों के दुरुपयोग, बिना चिकित्सकीय सलाह एंटीबायोटिक सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव तथा प्रतिबंधित दवाओं के अवैध विक्रय से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई, साथ ही दवाओं का विक्रय केवल वैध चिकित्सकीय प्रिस्क्रिप्शन पर करने और रिकॉर्ड अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए, इसके अलावा एक मैडिकल स्टोर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना के स्टोर एवं ओपीडी फार्मसी का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान औषधियों के सुरक्षित संभारण, तापमान नियंत्रण एवं रिकॉर्ड व्यवस्था की जांच की गई, वहीं लोकल परचेज से प्राप्त दो औषधियों के नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए संग्रहित किए गए, जन-जागरूकता अभियान के दौरान आमजन को नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तथा बिना चिकित्सकीय सलाह दवा सेवन से होने वाले खतरों के प्रति भी जागरूक किया गया।

केंद्र से करोड़ों की मंजूरी: फिर भी मुआवजे के लिए भटक रहे एनएच प्रभावित

एनएच परियोजना में जमीन गई, मुआवजा अब भी अधूरा

फाइलों में भुगतान पूरा, जमीन पर हितग्राही परेशान

कोरिया-MCB में एनएच मुआवजा बना उलझन, स्वीकृति के बाद भी इंतजार

मार्च में अप्रुवल, मई में भी भुगतान अधूरा

राष्ट्रीय राजमार्ग बना, लेकिन भू-स्वामियों का मुआवजा अटका

करोड़ों की राशि स्वीकृत, फिर भी कार्यालयों के चक्कर काट रहे प्रभावित



-रवि सिंह-

कोरिया/एमसीबी, 10 मई 2026

(घटती-घटना)। कोरिया और एमसीबी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से प्रभावित सैकड़ों भू-स्वामियों के लिए मुआवजा अब सिर्फ सरकारी फाइलों का विषय बनकर रह गया है। केंद्र सरकार द्वारा मार्च माह में करोड़ों रुपये की लिबत राशि को स्वीकृति दिए जाने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि वर्षों से अटका भुगतान अब शीघ्र पूरा हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी उलझी हुई नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति यह है कि कई हितग्राही अब भी यह जानने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं कि उनका भुगतान आखिर किस श्रेणी में लिबत है, मूल मुआवजा, संशोधित अवार्ड या फिर आर्बिट्रेशन प्रकरण, विभागीय दस्तावेजों में करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत और प्रक्रिया में दिखाई दे रही है, लेकिन अनेक

प्रभावित परिवारों के बैंक खाते अब भी खाली हैं।

केंद्र सरकार की स्वीकृति से जगगी थी उम्मीद

राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-43 (पुराना एनएच-78) के एमपीसीबी बॉर्डर से सूरजपुर सेक्शन तक सड़क चौड़ीकरण और उन्नयन कार्य के लिए केंद्र सरकार ने संशोधित लागत प्रस्ताव को मंजूरी दी, मंत्रालय स्तर से जारी स्वीकृति में भूमि अधिग्रहण मद में भारी राशि का प्रावधान भी किया गया, दस्तावेजों में यह स्पष्ट है कि परियोजना के लिए द्वितीय संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी प्रदान की गई तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी व्यय को बढ़ाया गया, इससे प्रभावित लोगों को उम्मीद जगी कि वर्षों से लिबत मुआवजा अब मिल सकेगा, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब स्वीकृति, पत्राचार और भुगतान प्रस्ताव की

प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, तब आखिर भुगतान जमीन पर क्यों नहीं पहुंचा?

विभागीय पत्रों में बार-बार शीघ्र भुगतान का उल्लेख

दस्तावेजों में एक ओर महत्वपूर्ण बात सामने आती है, विभिन्न अधिकारियों द्वारा जारी पत्रों में कई बार शीघ्र भुगतान और राशि जमा कराने का उल्लेख किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि विभागीय स्तर पर भी भुगतान लिबत रहने की स्थिति को लेकर चिंता थी, कुछ पत्रों में यह तक उल्लेख है कि प्रभावित भू-स्वामी लगातार आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और कलेक्टर स्तर की बैठकों में भी भुगतान का मुद्दा उठाया जाता रहा है, यानी फाइलों में समस्या का उल्लेख लगातार होता रहा, लेकिन समाधान अब तक पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर सका।

करोड़ों की राशि के दस्तावेज...लेकिन हितग्राही अब भी परेशान

विभागीय रिकॉर्ड में लगभग 12 करोड़ रुपये तथा करीब 4.56 करोड़ रुपये की राशि जमा कराने और भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ाने का उल्लेख सामने आया है, हेड रिजिस्ट्रार, रिवाइज्ड डाटा एंटी फॉर्म और विभागीय पत्राचार में यह राशि भू-स्वामियों के भुगतान हेतु दर्शाई गई है,

इसके बावजूद कई ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब तक वास्तविक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, कुछ प्रभावित परिवारों का आरोप है कि उन्हें समय पर यह तक नहीं बताया गया कि कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं और किस प्रक्रिया के तहत भुगतान होना है, ग्रामीणों के

अनुसार कई बार बैंक खाता, आधार, भूमि दस्तावेज और अन्य आवश्यक अभिलेख जमा कराने के बाद भी फाइल आगे नहीं बढ़ी, कई हितग्राहियों का कहना है कि विभागीय स्तर पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से लोग लगातार भ्रम की स्थिति में हैं।

ब्याज और अतिरिक्त वित्तीय भार का भी सवाल

लंबे समय तक भुगतान लिबत रहने से अब एक बड़ा वित्तीय सवाल भी खड़ा हो रहा है, यदि मुआवजा भुगतान में देरी हुई है और मामले न्यायालयीन प्रक्रिया तक पहुंचे हैं, तो भविष्य में ब्याज और अतिरिक्त भुगतान का भार भी बढ़ सकता है, विशेषज्ञों का मानना है कि भूमि अधिग्रहण मामलों में देरी केवल प्रशासनिक समस्या नहीं होती, बल्कि इससे परियोजना लागत भी बढ़ती है और शासन पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है।

न्यायालयीन प्रक्रिया का सम्मान, लेकिन लोगों का धैर्य जवाब दे...

मामला न्यायालयीन विचारधीन होने के कारण प्रभावित पक्ष खुलकर आक्रोश व्यक्त करने से बच रहे हैं, अधिकांश लोग न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए संयमित रूप से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों तक जमीन चली जाने के बाद भी यदि मुआवजा अधूरा रह जाए, तो परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों स्तर पर प्रभावित होते हैं। कई परिवारों का कहना है कि सड़क बन गई, गाड़ियां दौड़ने लगीं, लेकिन जिनकी जमीन गई वे आज भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।

लोगों की मुख्य मांगें...

प्रभावित हितग्राहियों ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि लिबत मूल मुआवजा प्रकरणों की स्पष्ट सूची जारी की जाए, आर्बिट्रेशन और सामान्य मुआवजा मामलों को अलग-अलग सार्वजनिक किया जाए, ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर दस्तावेज सत्यापन किया जाए, पत्राचार हितग्राहियों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए, भुगतान की स्थिति ऑनलाइन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाए, अब देखना यह होगा कि करोड़ों की स्वीकृति और लंबे विभागीय पत्राचार के बाद प्रशासन जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाने में कितनी तेजी दिखाता है, क्योंकि सड़क परियोजना तो पूरी हो चुकी है, लेकिन मुआवजे की सड़क अब भी कई हितग्राहियों के लिए अधूरी दिखाई दे रही है।

आर्बिट्रेशन और मूल मुआवजा में उलझे लोग

पूरे मामले में सबसे बड़ा भ्रम आर्बिट्रेशन प्रकरण और मूल मुआवजा को लेकर बताया जा रहा है, हाल में जारी स्वीकृतियों और पत्राचार में मुख्य रूप से कुछ आर्बिट्रेशन मामलों का उल्लेख सामने आया है, जबकि अनेक प्रभावित परिवारों का दावा है कि उनका मूल मुआवजा ही अभी तक लिबत है, ग्रामीणों का कहना है कि जिन मामलों में न्यायालयीन आदेश या संशोधित अवार्ड जारी हुए, उन पर विभागीय प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ी दिखाई देती है, लेकिन कई सामान्य भू-स्वामियों को अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि उनका प्रकरण किस स्थिति में है, यही कारण है कि प्रभावित लोग आज भी तहसील, एसडीएम कार्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और कलेक्टर कार्यालय के बीच भटकते नजर आ रहे हैं।

जिनके संपर्क में हों...उन्हें सूचित कर दीजिए...

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी तेज है कि विभागीय स्तर से मौखिक रूप से कुछ लोगों तक सूचना पहुंचाई जा रही है कि जिन हितग्राहियों का संपर्क उपलब्ध है, उन्हें मुआवजा संबंधी जानकारी दी जाए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें अब तक न तो आधिकारिक सूचना मिली और न ही भुगतान प्रक्रिया की स्पष्ट स्थिति बताई गई, इससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, कई प्रभावितों का कहना है कि यदि प्रशासन ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक सूचना जारी करे, पत्राचार हितग्राहियों की सूची प्रकाशित करे और भुगतान की वास्तविक स्थिति बताए, तो भ्रम की स्थिति काफी हद तक समाप्त हो सकती है।

सचिवों की मनमानी से प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल खड़गवां जनपद पंचायत में सीईओ के आदेश की उड़ रही धज्जियां!



-राजेश शर्मा-

खड़गवां, 10 मई 2026

(घटती-घटना)।

खड़गवां जनपद पंचायत में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, यहां पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के आदेशों की खुलेआम अनदेखी किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, आरोप है कि कई ग्राम पंचायत सचिव आदेशों का पालन करने के बजाय अपनी मनमानी पर उतारू हैं, जिससे जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली और अनुशासन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार पंचायतों में सीईओ द्वारा जारी निर्देशों का समय पर पालन नहीं किया जा रहा है, विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट, पंचायत अभिलेखों का संभारण, योजनाओं की मॉनिटरिंग और

वित्तीय दस्तावेजों से जुड़े मामलों में लगातार लापरवाही सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि कई सचिव आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे, जिससे शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सचिवों में आदेशों की अवहेलना करने का साहस कहाँ से आ रहा है? क्या उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई का भय नहीं है, या फिर जनपद स्तर पर अनुशासनात्मक व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है? स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी जोरों पर है कि कुछ सचिवों का प्रभाव इतना मजबूत है कि अधिकारी भी दबाव में नजर आते हैं, यदि ऐसा है तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि पंचायत व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न

माना जा रहा है, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब जनपद पंचायत के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के निर्देशों का ही पालन नहीं होगा, तो ग्रामीण विकास योजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी, इससे निर्माण कार्य, भुगतान प्रक्रिया और हितग्राही मूलक योजनाओं में अनिश्चितता बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, अब निगाहें जनपद पंचायत प्रशासन पर टिकी हैं। देखना होगा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदेशों की अवहेलना करने वाले सचिवों पर कारण बताओ नोटिस, वेतन रोकने अथवा निलंबन जैसी कार्रवाई करते हैं या फिर मामला केवल चर्चाओं तक सीमित रह जाएगा। लिलहाल पूरा मामला खड़गवां क्षेत्र में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।

वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत में हजारों प्रकरणों का निराकरण 5 करोड़ से अधिक का अवार्ड पारित



-संवाददाता-

सूरजपुर, 10 मई 2026

(घटती-घटना)।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय सूरजपुर में वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया, इस न्याय पर्व का शुभारंभ रमेश सिंह द्वारा वचुंअल माध्यम से किया गया, न्यायालय परिसर में विनीता वार्नर एवं समस्त न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में वरिष्ठ नागरिक संघ के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत की गई। इस दौरान अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी, बैंक, नगरपालिका एवं

विद्युत विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। **जिलेभर के न्यायालयों को किया गया शामिल**

यह नेशनल लोक अदालत केवल जिला एवं सत्र न्यायालय तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें कुटुम्ब न्यायालय, तालुका न्यायालय प्रतापपुर, बाल न्यायालय तथा जिले के सभी राजस्व न्यायालयों को भी शामिल किया गया, आयोजन का उद्देश्य वर्षों से लिबत मामलों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति से त्वरित और सरल निराकरण करना था।

मोटर दुर्घटना दावों में पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत

लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के कई मामलों का निराकरण करते हुए पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की गई, खण्डपीठ क्रमांक 1 में पति की दुर्घटना में मृत्यु से संबंधित वर्षों पुराने मामले का 17 लाख 50 हजार रुपये में समझौता कराया गया, वहीं खण्डपीठ क्रमांक 3 में एक अन्य मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में पत्नी को 21 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया, खण्डपीठ क्रमांक 4 में 6 लाख 70 हजार रुपये में समझौता हुआ, जबकि खण्डपीठ क्रमांक 6 में दो अलग-अलग मामलों में 11 लाख एवं 13 लाख 50 हजार रुपये में निपटारा कराया गया। इसके अतिरिक्त अन्य

खण्डपीठों में भी सैकड़ों मामलों का समझौते के आधार पर निराकरण हुआ।

दिव्यांग बालेश्वर सिंह को मिली मोटराइज्ड ट्राय साइकिल

समाज कल्याण विभाग सूरजपुर के सहयोग से ग्राम मसिरा निवासी बालेश्वर सिंह को माननीय न्यायाधीशों के हार्थों मोटराइज्ड ट्राय साइकिल प्रदान की गई, कुछ वर्ष पूर्व पेटु से गिरने के कारण उनकी कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर चुका था, जिससे वे चलने-फिरने में असमर्थ थे, राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर ट्राय साइकिल मिलने से उनके चेहरे पर खुशी लौट आई। उन्होंने न्यायाधीशों एवं समाज कल्याण विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

33 खण्डपीठों में हुई विभिन्न मामलों की सुनवाई

त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में कुल 33 खण्डपीठों का गठन किया गया था, इन खण्डपीठों में सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, राजीनामा योग्य आपराधिक एवं राजस्व प्रकरणों के साथ-साथ बैंक, बिजली, टेलीफोन एवं जल कर बकाया से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामलों की सुनवाई की गई, खण्डपीठों ने दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला और हजारों मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया।



83 हजार से अधिक पक्षकार हुए लाभान्वित

द्वितीय नेशनल लोक अदालत में जिलेभर से कुल 2587 लिबत प्रकरण एवं 92592 प्री-लिटिगेशन प्रकरण विचारार्थ रखे गए थे, इनमें से 83580 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया, इस दौरान कुल 5 करोड़ 09 लाख 33 हजार 428 रुपये का अवार्ड पारित किया गया, जिससे 83 हजार 580 से अधिक पक्षकार लाभान्वित हुए, इस सफल आयोजन का श्रेय विनीता वार्नर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूरी टीम को दिया जा रहा है।

75 साल बाद चिरमिरी में पहुंचेगी सरकारी बिजली, 53 करोड़ से बदलेगी तस्वीर....

SECL क्षेत्र के हजारों परिवारों को बड़ी राहत, अब CSPDCL से मिलेगी नियमित बिजली...

- कोयले की नगरी अब होगी सचमुच रोशन, चिरमिरी को मिली सरकारी बिजली की सौगात
- मुख्यमंत्री साय के संकल्प से चिरमिरी में 'रोशनी की आज़ादी', हर वार्ड तक पहुंचेगी बिजली
- जिस धरती ने देश को रोशन किया, अब वही चिरमिरी खुद होगी जगमग...
- 53.57 करोड़ की ऐतिहासिक परियोजना से चिरमिरी में शुरू होगा विकास का नया दौर

चिरमिरी में विकास की नई रोशनी, हर घर तक पहुंचेगा सरकारी बिजली

साय सरकार का बड़ा फैसला : चिरमिरी के सभी वार्डों में बिछेगा सरकारी बिजली नेटवर्क

75 साल का इंतज़ार खत्म

चिरमिरी को मिलेगी 'रोशनी की आज़ादी'

अब हर वार्ड में पहुंचेगी सरकारी बिजली

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संकल्प और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से बदल रही है चिरमिरी की तस्वीर

₹53.57 करोड़ की ऐतिहासिक परियोजना से चिरमिरी में शुरू होगा विकास का नया दौर

- सभी वार्डों में बिजली CSPDCL का नेटवर्क
- नए ट्रांसफार्मर, केबल स्वयं और पोल का निर्माण
- नियमित और स्वामी विकली आपूर्ति सुनिश्चित
- हजारों परिवारों को नियमित बिजली का अधिकार

डोमनहिल, गेल्लापानी, कोरिया कॉलरी, पोड़ी जैसे दूरस्थ क्षेत्र भी होंगे रोशन

वर्ष 2026-27 में प्रारंभ होगा कार्य

यह सिर्फ सरकारी बिजली नहीं है, यह चिरमिरी के लोगों को उनका हक मिलना है। आज़ादी के बाद से जो सपना अधूरा था, वो अब मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि और संवेदनशीलता से पूरा हो रहा है।

- श्याम बिहारी जायसवाल
स्वास्थ्य मंत्री एवं विधायक, चिरमिरी

चिरमिरी, 10 मई 2026 (घटती-घटना)
देश को कोयले से रोशन करने वाली धरती चिरमिरी अब खुद रोशनी की नई इबारत लिखने जा रही है, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक एस.ई.सी.एल. क्षेत्र के आसपास बसे हजारों परिवार सरकारी बिजली सुविधा से वंचित रहे, पीढ़ियां बीत गईं, सरकारें बदलती रहीं, योजनाएं आती-जाती रहीं, लेकिन चिरमिरी के कई वार्डों में रहने वाले लोगों के घरों तक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की नियमित सरकारी बिजली कभी नहीं पहुंच सकी। अब 75 वर्षों बाद वह ऐतिहासिक क्षण आने जा रहा है, जब चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्ड सरकारी बिजली नेटवर्क से जुड़े, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संकल्प और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के लगातार प्रयासों से यह बहुप्रतीक्षित सपना अब धरातल पर उतरने जा रहा है।

कोयले की नगरी, लेकिन अंधेरे में जीवित

चिरमिरी को देशभर में कोयला नगरी के रूप में जाना जाता है, यहां की खदानों से निकला कोयला देशकों से उद्योगों, बिजलीघरों और शहरों को ऊर्जा देता रहा है। विडंबना यह रही कि जिस क्षेत्र ने पूरे देश को रोशन किया, उसी

मुख्यमंत्री की घोषणा बनी उम्मीद की किरण

09 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के प्रवास के दौरान पहली बार इस मुद्दे पर बड़ा ऐलान हुआ, नगर निगम चिरमिरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के माध्यम से पूरे क्षेत्र में सरकारी बिजली आपूर्ति की घोषणा की, उस समय यह घोषणा केवल एक सरकारी घोषणा नहीं थी, बल्कि हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की नई रोशनी थी, वर्षों से उपेक्षित क्षेत्र के लोगों को पहली बार लगा कि शायद अब उनका सपना सच हो सकेगा, मुख्यमंत्री ने उस दौरान कहा था कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और चिरमिरी में सरकारी बिजली पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता होगी।

क्षेत्र के हजारों लोग बुनियादी बिजली सुविधा के लिए संघर्ष करते रहे, एस.ई.सी.एल. क्षेत्र के आसपास बसे डोमनहिल, गेल्लापानी, कोरिया कॉलरी, पोड़ी और अन्य वार्डों में रहने वाले लोगों की जिंदगी खदान प्रबंधन की पुरानी विद्युत व्यवस्था पर निर्भर थी, यह बिजली व्यवस्था अक्सर बाधित रहती थी, कई बार घंटों तक बिजली गुल रहती, जिससे बच्चों की पढ़ाई, व्यापार, घरेलू कामकाज और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती थीं, स्थानीय नागरिकों का कहना था कि वर्षों से वे यह सवाल पूछते रहे कि आखिर सरकारी बिजली उनके घरों तक क्यों नहीं पहुंच रही, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला।

हर घर तक पहुंचेगी सरकारी बिजली-

परियोजना पूरी होने के बाद चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्ड सीधे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, इससे लोगों को नियमित और स्थायी बिजली सुविधा मिलेगी, स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वर्तमान में खदान क्षेत्र की बिजली व्यवस्था पर निर्भरता के कारण आए दिन तकनीकी समस्याएं सामने आती थीं, कई क्षेत्रों में लो-वोल्टेज और बार-बार बिजली कटौती आम बात थी, अब सरकारी नेटवर्क बनने से लोगों को राहत मिलेगी, घरों में बिजली उपकरण बेहतर तरीके से चल सकेंगे, विद्यार्थियों को पढ़ाई में सुविधा होगी और छोटे व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया आभार-

क्षेत्रीय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल बिजली परियोजना नहीं, बल्कि चिरमिरी की जनता को उनका वरदान अधिकार दिलाने जैसा है, उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से जो सपना अधूरा था, वह अब पूरा होने जा रहा है, मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि और संवेदनशीलता के कारण यह ऐतिहासिक कार्य संभव हो पाया है, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिरमिरी के लोगों ने वर्षों तक समस्याओं का सामना किया है, लेकिन अब क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और यह परियोजना उस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगी।

केबल लाइन और वितरण नेटवर्क तैयार किए जाएंगे, जिससे पूरे नगर निगम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, जानकारों के अनुसार यह परियोजना केवल बिजली व्यवस्था तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

बदलेगा जीवन स्तर, बढ़ेगी सुविधाएं : विशेषज्ञों का मानना है कि स्थायी सरकारी

बिजली व्यवस्था शुरू होने के बाद चिरमिरी क्षेत्र में जीवन स्तर में बड़ा सुधार आएगा, नियमित बिजली मिलने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, छोटे व्यवसाय और दुकानों को लाभ मिलेगा, घरेलू उपकरण सुचारु रूप से चल सकेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होगी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, इसके अलावा भविष्य में नए निवेश और विकास कार्यों की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

इतिहास में दर्ज होगा यह दिन

चिरमिरी के बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई सरकारें देखीं, लेकिन सरकारी बिजली का सपना हमेशा अधूरा ही रहा, अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि आने वाली पीढ़ियां उस परेशानी को नहीं झेलेंगी जो दशकों से लोग सहते आए हैं, जिस धरती ने देश को ऊर्जा दी, अब वही धरती खुद विकास और रोशनी के नए दौर में प्रवेश करने जा रही है, 53 करोड़ से अधिक की यह परियोजना केवल अधोसंरचना निर्माण नहीं, बल्कि चिरमिरी के आत्मसम्मान और अधिकार से जुड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, आज चिरमिरी की आंखों में जो चमक दिखाई दे रही है, वह केवल बिजली के बल्बों की नहीं, बल्कि वर्षों बाद पूरी हुई उम्मीदों की रोशनी है।

परसा कोल ब्लॉक के कार्यों पर उठे सवाल... तालाब निर्माण और वृक्षारोपण में अनियमितता के आरोप

करोड़ों के कार्यों में गुणवत्ता पर सदेह, ग्रामीण बोले... 'कागजों में ज्यादा, जमीन पर कम दिख रहा काम'

खड़गवां, 10 मई 2026 (घटती-घटना)
वन परिक्षेत्र खड़गवां अंतर्गत परसा कोल ब्लॉक क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कराए जा रहे तालाब निर्माण एवं वृक्षारोपण कार्य अब सवाल के घेरे में आ गए हैं, स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता, गुणवत्ता में लापरवाही और सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं, ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपये की लागत से कराए जा रहे इन कार्यों में तय मापदंडों और तकनीकी गुणवत्ता का पालन नहीं किया जा रहा है, कई स्थानों पर निर्माण कार्य अधूरा दिखाई दे रहा है, जबकि कागजों में काम पूरा दर्शाए जाने की चर्चा क्षेत्र में हो रही है।

बता दे की खड़गवां के परसा कोल ब्लॉक क्षेत्र में तालाब निर्माण और वृक्षारोपण कार्यों को लेकर उठे सवाल अब स्थानीय स्तर पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुके हैं, यदि ग्रामीणों के आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल निर्माण गुणवत्ता का मामला नहीं बल्कि सरकारी धन के उपयोग और योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न होगा, अब निगाहें प्रशासन और वन विभाग पर टिकी हैं कि क्या इन शिकायतों की गंभीरता से जांच होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

तालाब निर्माण की गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल

ग्रामीणों के अनुसार तालाब निर्माण कार्य में तकनीकी मानकों की अनदेखी की जा रही है, आरोप है कि तालाब के मेड़ निर्माण में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, स्थानीय लोगों ने बताया कि सामान्यतः तालाब के मेड़ के पटल पर काली मिट्टी डालकर उसे पानी से गीला कर मजबूत आधार तैयार किया जाता है, लेकिन कई निर्माण स्थलों पर यह प्रक्रिया अपनाई ही नहीं गई, इसके बजाय पास की साधारण

वन परिक्षेत्र खड़गवां, परसा कोल ब्लॉक में तालाब निर्माण व वृक्षारोपण कार्य में अनियमितता के आरोप

काली मिट्टी व पौधों की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, मेड़ बनकर नहीं, बल्कि बरताने से कुदरत का खतरा

तालाब निर्माण में मानकों की अनदेखी, अगूरी खुदाई

मेड़ के दोनों तरफ पत्थर पिचिंग सिर्फ नाम मात्र की

पूर्व के पौधों की जड़ें नहीं उखाड़ी गईं, मेड़ बनकर किया जा रहा वृक्षारोपण

जड़ें टोक से नहीं हटाने से पौधों की बुढ़ि पर पड़ने का खतरा

पत्थर पिचिंग सिर्फ दिखावे के लिए...

तालाब निर्माण कार्य में मेड़ के दोनों ओर पत्थर पिचिंग किया जाना अनिवार्य माना जाता है ताकि कटाव रोका जा सके, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पिचिंग कार्य केवल औपचारिकता बनकर रह गया है, कई जगहों पर पत्थरों की परत बेहद कमजोर और सीमित दिखाई दे रही है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिस स्तर की मजबूती करोड़ों की लागत वाले निर्माण में दिखाई देनी चाहिए, वह जमीन पर नजर नहीं आ रही।

वृक्षारोपण कार्य में भी खानापूर्ति के आरोप...

तालाब निर्माण के साथ-साथ वृक्षारोपण कार्य को लेकर भी ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं, आरोप है कि कई स्थानों पर पुराने पौधों की जड़ों को पूरी तरह हटाए बिना ही नए पौधारोपण के लिए गड्ढे बना दिए गए, स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमानुसार पुराने पौधों और जड़ों को पूरी तरह हटाकर भूमि को तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ जल्दबाजी और खानापूर्ति के तरीके अपनाए गए हैं, ग्रामीणों का कहना है कि यदि जड़ों की समुचित सफाई नहीं होगी तो नए पौधों की वृद्धि प्रभावित होगी और वृक्षारोपण अभियान केवल आंकड़ों तक सीमित रह जाएगा।

मिट्टी का उपयोग कर मेड़ तैयार कर दिया गया, जिससे बरसात के दौरान तालाब के फूटने का खतरा बना हुआ है, ग्रामीणों का कहना है कि यदि भारी बारिश हुई तो कमजोर मेड़ टिक नहीं पाएंगे और पूरा निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त हो सकता है।

जमीन पर कम, कागजों में ज्यादा काम

क्षेत्र में यह चर्चा भी तेज है कि कई कार्यों को कागजों में अधिक और जमीन पर कम दिखाया जा रहा है, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता की कमी है और संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा, लोगों का कहना है कि यदि समय-समय पर तकनीकी निरीक्षण होता तो निर्माण गुणवत्ता और कार्यप्रणाली में ऐसी शिकायतें सामने नहीं आती।

सरकारी राशि के दुरुपयोग की आशंका

स्थानीय ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई गंभीर अनियमितताएं सामने आ सकती हैं, ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा क्षेत्रीय विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन राशि का वास्तविक लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाया।

जांच और कार्रवाई की मांग...

ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, लोगों का कहना है कि सरकार योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र का विकास और पर्यावरण संरक्षण है, लेकिन यदि निर्माण कार्यों में ही लापरवाही होगी तो योजनाएं केवल कागजी उपलब्धि बनकर रह जाएंगी।

वन विभाग का पक्ष नहीं मिल सका

इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी खड़गवां से उनका पक्ष जानने के लिए मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, जिसके कारण उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।

दू-ए ऑफिसर कॉलोनी चोरी कांड का खुलासा विश्रामपुर पुलिस ने आरोपी को दबोचा...

-संवाददाता- सूरजपुर/विश्रामपुर, 10 मई 2026 (घटती-घटना)

थाना विश्रामपुर पुलिस ने दू-ए ऑफिसर कॉलोनी में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, आरोपी ने डॉक्टर के सरकारी क्वार्टर से नगदी चोरी करने के साथ-साथ दो मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देना स्वीकार किया है। जानकारी के अनुसार 07 अप्रैल 2026 को दू-ए ऑफिसर कॉलोनी निवासी डॉ. शुभांगी वर्मा ने थाना विश्रामपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 06 अप्रैल की शाम वह इमरजेंसी ड्यूटी के लिए अपने क्वार्टर में ताला लगाकर अस्पताल गई थीं, पूरी रात ड्यूटी करने के बाद अगले दिन सुबह जब वह वापस लौटीं तो क्वार्टर का दरवाजा खुला मिला, अंदर जांच करने पर आलमारी में रखे पर्से से करीब 40 हजार रुपये नगद गायब मिले, शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार सदिग्धों पर नजर रख रही थी, इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शिवनंदनपुर निवासी आदित्य साहनी घटना वाली रात सदिग्ध परिस्थिति में घूमता देखा गया था और घटना के बाद से फरार चल रहा है, 07 मई को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपाचे मोटरसाइकिल से विश्रामपुर क्षेत्र में घूम रहा है, पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया, पूछताछ में आरोपी आदित्य साहनी (19 वर्ष) ने क्वार्टर नंबर 39 का ताला तोड़कर घर में घुसने और पर्से से लगभग 40 हजार रुपये चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि चोरी की अधिकांश रकम वह खर्च कर चुका है, पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 7,500 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त सुगा रॉड बरामद कर जन्त कर लिया, इसके अलावा 03 मई को उसने अम्बिकापुर के गंगापुर कन्या परिसर से अपाचे मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 डीई 6352 चोरी की थी, जिसे बाद में पेट्रोल खत्म होने पर छोड़कर फरार हो गया था, जिसका उपयोग वह विश्रामपुर में कर रहा था, पुलिस ने चोरी की अपाचे बाइक भी बरामद कर ली है, पूरे मामले के खुलासे में थाना प्रभारी प्रकाश राठौर के नेतृत्व में पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्रवाई में एएसआई अशोक साहू सहित पुलिस स्टाफ सक्रिय रहा।

वरिष्ठता का खेल या घोटाला? खाद्य विभाग में 10 साल की उलटी सूची पर हाईकोर्ट सख्त

पहले नियुक्त अधिकारी पीछे, बाद वाले आगे! खाद्य विभाग की वरिष्ठता सूची पर बड़ा विवाद

हाईकोर्ट के आदेश से बड़े सवाल, किसने बनाई विवादित वरिष्ठता सूची?

खाद्य विभाग में प्रमोशन का खेल? अदालत पहुंचा 10 साल पुराना विवाद

गलत सूची, सीधी पदोन्नति और अब कोर्ट की एंट्री—खाद्य विभाग में मचा हड़कंप

वरिष्ठता सूची पर बवाल, स्थापना शाखा से लेकर अवर सचिव तक उठे सवाल

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में 'सीनियरिटी गेम' का खुलासा!

मेरिट दबाई या नियम तोड़े? हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग कटघरे में

2015 वाले पीछे, 2016 वाले आगे! अब कोर्ट ने मांगा पूरा हिसाब

विवादित वरिष्ठता सूची पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 60 दिन में पुनर्विचार के निर्देश

क्या गलत सूची के आधार पर हुए प्रमोशन? अब विभागीय व्यवस्था पर सवाल

वरिष्ठता विवाद ने खोली सिस्टम की परतें, विभाग में बढ़ी बेवैनी

हाईकोर्ट पहुंचा वरिष्ठता विवाद, अब जिम्मेदारी तय होने की मांग तेज

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची पर हाईकोर्ट सख्त

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण आदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है, इस मामले में याचिकाकर्ता अपर्णा आर्य, राखी ठाकुर और सरिता पटेल ने वर्ष 2021 में जारी वरिष्ठता सूची को चुनौती दी थी, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2015 में हुई थी, जबकि निजी प्रतिवादी वर्ष 2016 में नियुक्त हुए थे, इसके बावजूद उन्हें वरिष्ठता सूची में ऊपर स्थान दिया गया, मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे ने अपने 28 अप्रैल 2026 के आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं, न्यायालय ने कहा... कि वर्ष 2015 और 2016 की नियुक्तियां अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हुई थीं, ऐसे में दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को एक संयुक्त वरिष्ठता सूची में शामिल करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सामान्य सेवा शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12 के अनुरूप नहीं माना जा सकता, न्यायालय ने 18 नवंबर 2021 के आदेश को निरस्त करके हुए याचिकाकर्ताओं को नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी है, साथ ही संबंधित प्राधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह 60 दिनों के भीतर वरिष्ठता सूची पर पुनर्विचार कर निर्णय ले, यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिनकी वरिष्ठता अलग-अलग भर्ती वर्षों के बावजूद संयुक्त सूची में तय की गई है, विभागीय स्तर पर इस आदेश को भविष्य की वरिष्ठता और पदोन्नति प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वरिष्ठता का खेल या घोटाला? हाईकोर्ट के आदेश ने खोली खाद्य विभाग की परतें



वरिष्ठता का खेल या घोटाला? खाद्य विभाग में 10 साल की उलटी सूची, सीधी पदोन्नति



—न्यूज डेस्क—

रायपुर, 10 मई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में वर्षों से चल रहा वरिष्ठता एवं पदोन्नति विवाद अब बड़ा प्रशासनिक और कानूनी मुद्दा बन चुका है, विभाग में वर्ष 2015 से लेकर 2026 तक तैयार की गई वरिष्ठता सूची, पदोन्नति आदेश, मेरिट और आरक्षण रॉस्टर को लेकर उठे सवाल अब सीधे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तक पहुंच चुके हैं, अदालत द्वारा वरिष्ठता सूची पर पुनर्विचार के निर्देश दिए जाने के बाद विभागीय व्यवस्था, स्थापना शाखा और फाइल प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दैनिक घटती-घटना ने इस पूरे विवाद को लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अखबार द्वारा पहले ही यह सवाल उठाया गया था कि आखिर कैसे पहले नियुक्त अधिकारी पीछे और बाद में नियुक्त अधिकारी वरिष्ठता सूची में आगे पहुंच गए, अब जब मामला न्यायालय पहुंचा और अदालत ने भी पुनर्विचार का आदेश दे दिया, तब विभागीय निर्णयों की निष्पक्षता पर चर्चा और तेज हो गई है।

पहले नियुक्त अधिकारी पीछे, बाद वाले आगे बना सबसे बड़ा विवाद

विभागीय कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर पहले नियुक्त अधिकारियों को पीछे और बाद में नियुक्त अधिकारियों को आगे कैसे रखा गया, कर्मचारियों का कहना है कि वरिष्ठता सूची केवल नामों की सूची नहीं होती, बल्कि इसी के आधार पर पदोन्नति, प्रशासनिक अधिकार और भविष्य की सेवा संरचना तय होती है, सूत्रों के अनुसार

स्थापना शाखा की भूमिका पर गंभीर सवाल

इस पूरे विवाद में विभाग की स्थापना शाखा सबसे ज्यादा चर्चा में है, विभागीय सूत्रों के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार करने और पदोन्नति प्रस्तावों की प्रक्रिया इसी शाखा से संचालित होती है, यही कारण है कि अब यह सवाल उठ रहा है कि यदि लगातार शिक्षापूर्व और आपत्तियां सामने आ रही थीं तो स्थापना शाखा ने समय रहते रिकॉर्ड की समीक्षा क्यों नहीं की, विभागीय चर्चाओं में एडीसी वेणीगोम साहू की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, कर्मचारियों का कहना है कि फाइलें केवल औपचारिक रूप से आगे बढ़ाई गईं या फिर उनका गंभीर परीक्षण भी हुआ—यह अब जांच का विषय बन चुका है, हालांकि अभी तक किसी अधिकारी की आधिकारिक जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, लेकिन विभागीय कर्मचारियों का मानना है कि यदि प्रारंभिक स्तर पर निष्पक्ष जांच और रिकॉर्ड परीक्षण हुआ होता तो मामला अदालत तक नहीं पहुंचता।

विवादित सूची के आधार पर आगे चलकर पदोन्नति आदेश भी जारी हुए, यही वजह है कि अब प्रमोशन प्रक्रिया भी सवालियों के घेरे में आ गई है, कर्मचारियों का आरोप है कि यदि वरिष्ठता सूची में त्रुटि थी तो उसी आधार पर हुए पदोन्नति आदेशों की वैधता पर भी प्रश्न उठाना स्वाभाविक है।

क्या मेरिट सूची और आरक्षण रॉस्टर की अनदेखी हुई?

विभाग के भीतर यह चर्चा भी तेज है कि वरिष्ठता निर्धारण में मेरिट सूची और आरक्षण रॉस्टर का सही पालन नहीं हुआ, कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि चयन सूची और अंतिम वरिष्ठता सूची में अंतर दिखाई देता है, हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अदालत द्वारा पुनर्विचार के निर्देश दिए जाने के बाद यह पूरा मामला और संवेदनशील हो गया है, कर्मचारियों का कहना है कि यदि पुनर्विचार प्रक्रिया में पुराने रिकॉर्ड, चयन सूची, नियुक्ति आदेश और आरक्षण रॉस्टर की निष्पक्ष जांच होती है तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

अवर सचिव की भूमिका पर भी उठे सवाल

इस पूरे विवाद में अब विभागीय अवर सचिव की भूमिका को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है, कर्मचारियों का कहना है कि पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़े फाइलें कई प्रशासनिक स्तरों से गुजरते हुए अवर सचिव तक पहुंचती हैं, ऐसे में यदि लगातार शिक्षापूर्व सामने आ रही थीं तो क्या उस स्तर पर स्वतंत्र जांच और स्कूटनी नहीं होनी चाहिए थी? सूत्रों के अनुसार विभाग के भीतर यह सवाल उठ रहा है कि क्या पुराने स्तरों से आई फाइलों को बिना गहन परीक्षण के आगे बढ़ा दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि अवर सचिव स्तर केवल हस्ताक्षर की औपचारिकता नहीं होता, बल्कि वहां पर नियमों और प्रक्रिया की वैधानिक समीक्षा भी अपेक्षित होती है, यही कारण है कि अब विभागीय कर्मचारियों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर प्रशासनिक स्तर पर कहां-कहां चूक हुई।

क्या यह केवल गलती थी या सुनियोजित प्रक्रिया?

पूरा मामला अब इसी प्रश्न पर आकर टिक गया है कि क्या यह केवल प्रशासनिक त्रुटि थी या फिर किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली सुनियोजित प्रक्रिया? यदि यह गलती थी तो वर्षों तक सुधार क्यों नहीं हुआ? यदि शिकायतें थीं तो जांच क्यों नहीं हुई? यदि नियम स्पष्ट थे तो मामला अदालत तक क्यों पहुंचा? इन्हीं सवालों के कारण अब कर्मचारियों संगठन पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग उठा रहे हैं।

पदोन्नति आदेश भी विवाद में...

सूत्रों के अनुसार विवादित वरिष्ठता सूची के आधार पर जारी कुछ पदोन्नति आदेशों पर भी सवाल उठ रहे हैं, कर्मचारियों का कहना है कि यदि मूल वरिष्ठता सूची ही विवादित है तो उसके आधार पर जारी पदोन्नति आदेशों की भी समीक्षा होना आवश्यक है, कुछ कर्मचारियों संगठन अब पूरे प्रमोशन रिकॉर्ड, फाइल भूयंठ और प्रशासनिक अनुमोदन प्रक्रिया की जांच की मांग कर रहे हैं।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग में बढ़ा दबाव

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब विभागीय अधिकारियों पर निष्पक्ष पुनर्विचार का दबाव बढ़ गया है, कर्मचारियों का कहना है कि अब विभाग को रिकॉर्ड की पारदर्शी समीक्षा करनी होगी, विभागीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि यदि वरिष्ठता सूची में बदलाव होता है तो उसका असर पुराने प्रमोशन, पदक्रम और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

दैनिक घटती-घटना की खबरों को मिली मजबूती

दैनिक घटती-घटना ने इस पूरे विवाद को लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया था, अखबार ने पहले ही वरिष्ठता सूची, मेरिट विवाद, स्थापना शाखा की भूमिका और पदोन्नति आदेशों को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे, अब अदालत द्वारा पुनर्विचार के निर्देश दिए जाने के बाद अखबार द्वारा उठाए गए मुद्दों को और मजबूती मिली है, विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि यदि यह मामला लगातार सार्वजनिक नहीं होता तो शायद विवाद दबा रह जाता।

क्या होगी स्वतंत्र जांच?

वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विभाग केवल औपचारिक पुनर्विचार करेगा या फिर पूरे मामले की स्वतंत्र जांच भी होगी, कर्मचारियों संगठनों का एक वर्ग अब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा या स्वतंत्र प्रशासनिक जांच की मांग उठा रहा है, हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।

अब सबकी नजर अगले फैसले पर

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग न्यायालय के निर्देशों के बाद क्या कदम उठाता है, क्या वरिष्ठता सूची बदलेगी? क्या विवादित प्रमोशन आदेशों की समीक्षा होगी? क्या जिम्मेदारी तय होगी?

क्या फाइल प्रक्रिया की जांच होगी?

इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का यह वरिष्ठता विवाद अब केवल विभागीय असंतोष का मामला नहीं रहा। यह अब प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सरकारी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्न बन चुका है।

शराब की प्लास्टिक बोतल योजना फेल छत्तीसगढ़ में 65 प्रतिशत घटा उत्पादन

रायपुर, 10 मई 2026। छत्तीसगढ़ में शराब विक्री को लेकर आबकारी विभाग का नया प्रयोग अब खुद विभाग और डिस्ट्रिलरीज के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। कांच की बोतलों की जगह प्लास्टिक (फाइबर) बोतलों में देशी शराब बेचने का फैसला लागू होते ही उत्पादन और सप्लाई व्यवस्था लड़खड़ा गई है। हालात यह हैं कि राज्य में देशी शराब का उत्पादन करीब 65 प्रतिशत तक प्रभावित हो गया है और कई दुकानों में लोगों को उनकी पसंद का ब्रांड तक नहीं मिल पा रहा। 1 अप्रैल से इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। विभाग का तर्क था कि प्लास्टिक बोतलें हल्की होती हैं, टूटती नहीं हैं और परिवहन में खर्च भी कम आता है। लेकिन जमीन पर यह फैसला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार राज्य की पांच प्रमुख डिस्ट्रिलरीज इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। दरअसल, शराब की बॉटलिंग के लिए जो मशीनें और सिस्टम लगाए गए हैं, वे कांच की बोतलों के हिसाब से डिजाइन किए गए थे। अब उन्हीं मशीनों में हल्की प्लास्टिक बोतलें रखने पर वे बार-बार गिर रही हैं, जिससे बॉटलिंग की पूरी प्रक्रिया धीमी हो गई है।

बाजार में पसंदीदा ब्रांड की किल्लत

उत्पादन कम होने का असर अब बाजार में भी दिखाई देने लगा है। कई शराब दुकानों में देशी शराब के लोकप्रिय ब्रांड उपलब्ध नहीं हैं। शराब कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि सप्लाई प्रभावित होने से दुकानों में स्टॉक की कमी लगातार बढ़ रही है।

प्लास्टिक बनाम कांच की बहस तेज

इस फैसले के बाद अब कांच और प्लास्टिक बोतलों को लेकर बहस भी तेज हो गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक कांच की बोतलें शराब भंडारण के लिए ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं, क्योंकि कांच शराब के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करता और लंबे समय तक स्वाद एवं गुणवत्ता बनाए रखता है। वहीं प्लास्टिक बोतलों को हल्का और सस्ता जरूर माना जाता है।

देश की प्रगति और राष्ट्रीय एकता में क्षत्रिय कुर्मी समाज का योगदान अविस्मरणीय : सीएम साय

रायपुर, 10 मई 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कबीरधाम जिले के डोंगरिया में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज की एकता, संगठन, सामाजिक चेतना तथा देश और प्रदेश के विकास में कुर्मी समाज के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि एक संगठित और सशक्त समाज ही मजबूत राष्ट्र की आधारशिला होता है। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों को सिंचाई, सड़क और धार्मिक पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगात भी दी। इससे पूर्व उन्होंने जलेश्वर महादेव धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया तथा प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कुर्मी समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज और



लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जैसी महान विभूतियों ने देश की एकता, सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज मेहनतकश, प्रगतिशील और जागरूक समाज है, जिसने खेती-किसानी से लेकर शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक नेतृत्व तक हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के नए दौर से गुजर रहा है। अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रतीक बना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रामलला दर्शन योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन करा रही है तथा अब तक लगभग 42 हजार श्रद्धालु इसका लाभ ले चुके हैं।

महासमुंद एलपीजी घोटाले का मास्टरमाइंड निकला फूड ऑफिसर

ढाबे पर हुई 92 टन गैस की डील, 3 दिन में खाली किए 6 टैंकर

रायपुर, 10 मई 2026।

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में जल एलपीजी गैस कैम्पल टूकों से करोड़ों रुपए की गैस गायब होने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव को पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया गया है। आरंग के एक ढाबे में 92 टन गैस की डील हुई और 3 दिन में कैम्पल खाली हो गए। पुलिस के मुताबिक, खाद्य अधिकारी ने गौरव गैस एजेंसी के संचालक पंकज चौधरी, रायपुर निवासी मनीष चोधरी और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर करीब डेढ़ करोड़ रुपए की गैस का गबन किया। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि



संतोष ठाकुर और सार्धक ठाकुर अब भी फरार हैं। पुलिस के अनुसार, दिसंबर 2025 में सिंधोड़ा थाना क्षेत्र में 6 एलपीजी गैस से भरे कैम्पल टूक जब्त किए गए थे। भीषण गर्मी और सुरक्षा कारणों से इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्देश कलेक्टर कार्यालय से खाद्य विभाग को दिए गए।

रिश्वत लेते हुए एसआई हुआ गिरफ्तार



मारपीट के मामले को रफा-दफा करने के लिए मांग रहा था पैसा...

बिलासपुर/सक्ती, 10 मई 2026। सक्ती जिले के थाना चंद्रपुर में पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक को एंटी कर्प्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी एसआई एसमन मिश्रा पर मारपीट के एक मामले को रफादफा करने के बदले 40 हजार रुपये रिश्वत

मांग रहा था। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम बालपुर निवासी शिव प्रसाद बरेठ ने बिलासपुर स्थित एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम बालपुर निवासी सरस्वती जायसवाल द्वारा उनके तथा परिवार के सदस्यों के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट थाना चंद्रपुर में दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि मामले में कड़ी कार्रवाई से बचाने और राहत दिलाने के बदले एसआई एसमन मिश्रा द्वारा 40

हजार रुपये की मांग की जा रही थी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें आरोपी द्वारा पहली किशत के रूप में 20 हजार रुपये लेने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी टीम ने ट्रेप की योजना बनाई। शनिवार 09 मई को शिकायतकर्ता को आरोपी ने चंद्रपुर स्थित गुड्डू ढाबा बुलाया। यहां दूसरी किशत के रूप में 20 हजार रुपये लेते समय एसीबी की टीम ने आरोपी एसआई को रो हथौड़े गिरफ्तार कर लिया।